

वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन मजदूर यूनियन, पटना

बनाम

श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. का प्रबंधन एवं अन्य

24 नवंबर, 1983

[डी.ए. देसाई, आर.बी. मिश्र, और रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्तिगण]

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

क्या अधिनियम बोनस से संबंधित विधि पर संपूर्ण है - अधिनियम से पूर्व दिया जा रहा 'उपस्थिति बोनस' - क्या कर्मचारी अधिनियम के तहत देय लाभ बोनस के अतिरिक्त 'उपस्थिति बोनस' के हकदार हैं।

प्रथम उत्तरदाता के प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मकारों को 'उपस्थिति बोनस' दिया जा रहा था। यह प्रश्न कि क्या कर्मकार 'उपस्थिति बोनस' के अतिरिक्त बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के तहत बोनस के भुगतान के हकदार थे, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित किया गया था। न्यायाधिकरण ने कर्मकारों के पक्ष में निर्णय दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष नियोक्ता ने तर्क दिया कि जब अधिनियम के तहत बोनस का भुगतान किया जा रहा था, तब कर्मकार अलग से 'उपस्थिति बोनस' के हकदार नहीं थे। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के *सांघी जीवराज घीवर चंद एवं अन्य बनाम सचिव, मद्रास चिलीज, ग्रेन्स किराना मर्चेन्ट्स वर्कर्स यूनियन एवं एक अन्य [(1969) 1 एस.सी.आर. 366]* में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि कर्मकार 'उपस्थिति बोनस' के भुगतान के हकदार नहीं थे।

अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित: 1. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने समवर्ती रूप से यह माना कि प्रतिष्ठान में कर्मकार पहले से ही 'उपस्थिति बोनस' प्राप्त कर रहे थे। 'उपस्थिति

बोनस' बोनस अधिनियम के दायरे से बाहर होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के पंचाट को रद्द करना सही नहीं था। [928 ई- एफ, 931 ए]

2. घीवर चंद के मामले में, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया, प्रश्न यह नहीं था कि बोनस अधिनियम के लागू होने के बाद, अब तक भुगतान किए गए अन्य प्रकार के बोनस देय होंगे या नहीं। इस प्रश्न पर सीधे *मुंबई कामगार सभा, बॉम्बे बनाम मेसर्स अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई एवं अन्य [(1976) 3 एस.सी.आर. 591]* में विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम प्रथागत बोनस को अछूता छोड़ देता है। [929 ए- बी, 930 एच]

3. वर्तमान मामले में, यदि नियोक्ता ने पंचाट को चुनौती नहीं दी होती, तो कर्मकारों को एक दशक से भी पहले बोनस का लाभ मिल गया होता। यह 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिए जाने को उचित ठहराता है। [931 बी- सी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1974 की दीवानी अपील संख्या 1851

1970 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 613 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 24 अक्टूबर, 1973 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता के लिए *आर.के. गर्ग और वी.जे. फ्रांस*।

उत्तरदाता के लिए *एल.सी. गोयल*।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बिहार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के एक पंचाट को रद्द कर दिया गया था, और कर्मकार संघ ने यह अपील दायर की है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत दो विवाद न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित किए गए थे, लेकिन अपील केवल एक तक सीमित है, अर्थात्, "क्या कर्मकार इस

प्रतिष्ठान में दिए जा रहे 'उपस्थिति बोनस' के अतिरिक्त बोनस संदाय अधिनियम के तहत वर्ष 1966-67 के लिए बोनस के भुगतान के हकदार हैं? यदि हाँ, तो बोनस की मात्रा क्या होनी चाहिए?" न्यायाधिकरण ने पाया कि कर्मकार बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) के तहत देय बोनस के अतिरिक्त उपस्थिति बोनस के हकदार थे, और संदर्भ के अनुसार आवश्यक राशि निर्दिष्ट की। नियोक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पंचाट को चुनौती दी और तर्क दिया कि जब अधिनियम के तहत बोनस का भुगतान किया जा रहा था, तब कोई अलग उपस्थिति बोनस देय नहीं था। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने न्यायाधिकरण से सहमति जताते हुए यह माना कि प्रतिष्ठान में कर्मकार पहले से ही उपस्थिति बोनस प्राप्त कर रहे थे और यह जांचने के लिए आगे बढ़ी कि क्या ऐसा उपस्थिति बोनस अधिनियम के तहत कर्मकारों को देय बोनस में शामिल था या वैधानिक बोनस के अतिरिक्त इसका दावा किया जा सकता था। इस न्यायालय के *सांघी जीवराज घीवर चंद एवं अन्य बनाम सचिव, मद्रास चिलीज, ग्रेन्स किराना मर्चेण्ट्स वर्कर्स यूनियन एवं एक अन्य* में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कर्मकार वर्ष 1966-67 के लिए उपस्थिति बोनस के भुगतान के हकदार नहीं थे और तदनुसार पंचाट को रद्द कर दिया।

घीवर चंद (उपरोक्त) के मामले में, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही देखा गया, विचारणीय प्रश्न यह नहीं था कि अधिनियम के लागू होने और वैधानिक बोनस देय होने के बाद, अब तक भुगतान किए गए अन्य प्रकार के बोनस देय नहीं रह गए। दूसरी ओर, बाद के एक मामले *मुंबई कामगार सभा, बॉम्बे बनाम मेसर्स अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई एवं अन्य* में इस न्यायालय ने सीधे प्रश्न पर विचार किया। बाद के मामले में घीवर चंद के मामले का भी उल्लेख किया गया और अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया:

1 [1969] आई एस.सी.आर. 366 .

2 [1976] 3 एस.सी.आर. 591.

"1965 के बोनस अधिनियम के विस्तृत शीर्षक से यह और स्पष्ट होता है कि यह 'कुछ प्रतिष्ठानों' में नियोजित व्यक्तियों को बोनस प्रदान करने का प्रयास करता है - सभी प्रतिष्ठानों में नहीं। इसके अलावा, प्रथागत बोनस के लिए लाभ या उपलब्ध अधिशेष की गणना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह लंबे समय के उपयोग पर आधारित भुगतान है और अक्सर त्यौहारों पर खर्च द्वारा उचित ठहराया जाता है; और अधिनियम त्यौहार बोनस की मात्रा तय करने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं देता है; न ही यह स्पष्ट रूप से ऐसे उपयोग को समाप्त करना चाहता है। निष्कर्ष काफी स्पष्ट प्रतीत होता है, जब तक कि हम न्यायिक सहानुभूति को इसके विपरीत न मोड़ें, कि बोनस अधिनियम केवल लाभ बोनस और उससे संबंधित मामलों से संबंधित है और प्रथागत, पारंपरिक या संविदात्मक बोनस को शासित नहीं करता है।"

घीवर चंद के मामले का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, ने इस बाद के मामले में संकेत दिया:

"..... इस प्रकार देखे जाने पर, हम घीवर चंद के निर्णय को लाभ-बोनस तक सीमित पढ़ने में कोई बाधा नहीं पाते हैं, जो प्रथागत बोनस के गैर-वैधानिक संचलन के लिए स्थान छोड़ता है। वह मामला कर्मकारों के दो समूहों द्वारा व्यवसाय के लाभ पर आधारित बोनस के दावे से संबंधित था, लेकिन वे कर्मकार स्पष्ट अपवर्जन या छूट के कारण कानून के दायरे से बाहर हो गए थे। किसी अन्य प्रकार के बोनस से संबंधित कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था और इसे विवक्षित रूप से तय किया गया नहीं माना जा सकता है। घीवर चंद को समझने की कुंजी के रूप में हमें जिस शासी सिद्धांत की सराहना करनी है, वह यह है कि यह उन प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित कर्मकारों के दो समूहों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत आग्रह किए गए

लाभ बोनस के मामले से संबंधित है, जिन्हें बोनस अधिनियम से या तो अपवर्जित किया गया है या छूट दी गई है। कानून का प्रमुख अव्यक्त आधार यह है कि यह केवल लाभ-आधारित बोनस से संबंधित है जैसा कि पहले विस्तार से समझाया गया है। बोनस अधिनियम में अन्य सभी प्रकार के बोनस को शून्य करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, न ही आवश्यक विवक्षा द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकलता है। वह व्यवस्था निस्संदेह कानून को इस प्रकार निर्धारित करती है:

'कानून के इतिहास, पृष्ठभूमि और उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिनमें अधिनियम बनाया गया था, अधिनियम के उद्देश्य और इसकी योजना को देखते हुए, उत्तरदाताओं की ओर से सुझाए गए उस अर्थ को स्वीकार करना संभव नहीं है कि अधिनियम अपने सभी पहलुओं में बोनस की विषय-वस्तु से व्यापक रूप से निपटने वाला एक संपूर्ण अधिनियम नहीं है या संसद ने अभी भी उन लोगों के लिए जिनके लिए अधिनियम अपने प्रावधानों के कारण लागू नहीं होता है, चाहे वह अपवर्जन के रूप में हो या छूट के रूप में, औद्योगिक विवाद अधिनियम या अन्य तदनुरूपी विधि के तहत औद्योगिक न्यायनिर्णयन के माध्यम से बोनस के संबंध में विवाद उठाने का विकल्प खुला रखा है।'

लेकिन संदर्भात्मक रूप से व्याख्या किए गए इस कथन का अर्थ यह है कि लाभ-बोनस, जो बोनस अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित नहीं है और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक विवाद के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, अब अनुमेय नहीं है। जब संसद ने बोनस अधिनियम से कुछ श्रेणियों को स्पष्ट रूप से अपवर्जित या छूट दी है, तो लाभ-आधारित बोनस के मामले में वे बाहर हो जाते हैं। आप पिछले दरवाजे के तरीके

से, अर्थात् औद्योगिक विवाद अधिनियम के तंत्र का सहारा लेकर लाभ-बोनस को पुनर्जीवित नहीं कर सकते।"

धीवर चंद के मामले के और विश्लेषण पर, न्यायमूर्ति अय्यर, ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला:

"अधिनियम की योजना और न्यायालय के तर्क का सूक्ष्म और ठोस विश्लेषण हमें इस संदेह में नहीं छोड़ता है कि यह प्रथागत बोनस को अछूता छोड़ देता है।"

हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं।

न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष पर कि उपस्थिति बोनस पहले से दिया जा रहा था और यह अधिनियम के दायरे से बाहर था, उच्च न्यायालय द्वारा पंचाट को रद्द करना सही नहीं था। अपील सफल होनी चाहिए और इस संबंध में पंचाट को बहाल किया जाना चाहिए। यदि नियोक्ता ने पंचाट को चुनौती नहीं दी होती, तो कर्मकारों को एक दशक से भी पहले बोनस का लाभ मिल गया होता। यह ब्याज दिए जाने को उचित ठहराता है। कर्मकारों की अपील को खर्च सहित स्वीकार करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि उपस्थिति बोनस के रूप में दिए जाने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा पाई गई राशि पर देय तिथि से भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। सुनवाई शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है।

एन.वी.के.

अपील स्वीकार।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।